



INTERNATIONAL JOURNAL OF TRENDS IN EMERGING RESEARCH AND DEVELOPMENT

INTERNATIONAL JOURNAL OF TRENDS IN EMERGING RESEARCH AND DEVELOPMENT

Volume 3; Issue 1; 2025; Page No. 147-152

Received: 12-10-2024

Accepted: 21-12-2024

ग्रामीण एवं शहरी भारत में स्वच्छ भारत मिशन का आर्थिक प्रभाव: एक मूल्यांकन

¹Durga Charan Mahato, ²Dr. Shweta Tripathi and ³Dr. Ram Singh Kushwaha

¹Research Scholar, Madhyanchal Professional University, Bhopal, Madhya Pradesh, India

^{2,3}Department of Economics, Madhyanchal Professional University, Bhopal, Madhya Pradesh, India

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16091090>

Corresponding Author: Durga Charan Mahato

सारांश

सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, भारत के प्रधान मंत्री ने 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। मिशन समन्वयक को पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (MDWS) के सचिव को दो उप-मिशनों, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के साथ दिया गया, जिसका उद्देश्य 2019 तक स्वच्छ भारत प्राप्त करना है, अध्ययन में विकास हस्तक्षेपों की दक्षता का अनुमान लगाने के लिए मानक आर्थिक मॉडलिंग विधियों को अपनाया गया। लागतों में शौचालय और हाथ धोने के स्टेशन के लिए निवेश और परिचालन लागत दोनों शामिल थे, जिसमें सरकार या गैर-राज्य अभिनेताओं द्वारा प्रदान की गई सब्सिडी या संसाधन, साथ ही घरों को वित्तीय और गैर-वित्तीय लागतें शामिल थीं।

मूलशब्द: स्वच्छता, स्वच्छ भारत, वित्तीय, आर्थिक स्थिति, केंद्रीय ग्रामीण

प्रस्तावना

स्वच्छ भारत मिशन एक सम्मानजनक मिशन है और स्वच्छ भारत मिशन के पीछे वित्तीय लाभों के अनुसार, प्रत्येक भारतीय को स्वच्छता के लिए लगातार कम से कम 100 घंटे समर्पित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। भारत के आम नागरिक के रूप में, मैं यह अनुमान लगा सकता हूँ कि यदि स्वच्छ भारत मिशन प्रभावी है, तो यह भारत के सभी नागरिकों के लिए लाभकारी होगा। कुल मिलाकर, इस अध्ययन ने यह प्रदर्शित किया है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) वित्तीय और आर्थिक दोनों दृष्टिकोण से असाधारण रूप से लागत-मूल्यवान है।

भारत सरकार द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, माननीय प्रधानमंत्री ने इस प्रयास का नेतृत्व करने के लिए कुछ चुनिंदा उल्लेखनीय व्यक्तियों के समूह का नाम चुना है। मृदुला सिन्हा, सचिन तेंदुलकर, बाबा रामदेव, शशि थरूर, अनिल अंबानी, कमल

हसन, सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा और टीम तारक मेहता का उल्टा चश्मा नौ आमंत्रित सार्वजनिक हस्तियाँ थीं। उन्होंने उनसे स्वच्छ भारत में योगदान देने, इसे सोशल मीडिया पर साझा करने और नौ अन्य लोगों को भी ऐसा करने के लिए आमंत्रित करने के लिए कहा, ताकि एक श्रृंखला बनाई जा सके।

सरकार का भारत 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सीआरएसपी) की शुरुआत मुख्य रूप से ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और महिलाओं को गोपनीयता और सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। 1999 से, "संपूर्ण स्वच्छता अभियान" (टीएससी) के तहत एक "मांग संचालित" दृष्टिकोण ने सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी), मानव संसाधन विकास (एचआरडी), क्षमता विकास गतिविधियों पर अधिक जोर दिया ताकि ग्रामीण जनता के बीच जागरूकता बढ़ाई जा सके और स्वच्छता सुविधाओं की मांग पैदा की जा सके।

इसने लोगों की आर्थिक स्थिति के अनुसार वैकल्पिक वितरण तंत्रों के माध्यम से उपयुक्त विकल्प चुनने की क्षमता को बढ़ाया। व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (आईएचएचएल) के निर्माण और उपयोग के लिए गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए गए। टीएससी के उत्तराधिकारी कार्यक्रम "निर्मल भारत अभियान" (एनबीए) निर्मल भारत अभियान (एनबीए) में निर्मल ग्राम पंचायत बनाने के उद्देश्य से संतृप्त परिणामों के लिए पूरे समुदाय को शामिल करने की परिकल्पना की गई थी। एनबीए के तहत, व्यक्तिगत पारिवारिक परिवारों के लिए प्रोत्साहन बढ़ाए गए और मनरेगा से और अधिक केंद्रित समर्थन प्राप्त किया गया। हालांकि, एनबीए को मनरेगा के साथ जोड़ने में कार्यान्वयन संबंधी कठिनाइयां थीं क्योंकि विभिन्न स्रोतों से मिलने वाले वित्तपोषण के कारण कार्यान्वयन तंत्र में देरी हुई।

साहित्य समीक्षा

कुमार टी. (2014) ^[1] ने "राष्ट्रीय मिशन के बारे में जागरूकता का अध्ययन करना: स्वच्छ भारत: निजी और पब्लिक स्कूलों के मिडिल स्कूल के छात्रों में स्वच्छ विद्यालय" में इस बात पर जोर दिया है कि यह सुनिश्चित करना कानून निर्माताओं, सरकारी अधिकारियों, निवासियों और अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को सुरक्षित पेयजल, अच्छी सफाई और स्वास्थ्य सुविधाओं वाले स्कूल तक पहुंच मिले।

इवने एट अल. (2014) ^[2] ने देश के दलित समुदाय पर स्वच्छ भारत अभियान के प्रभावों पर भी शोध किया और निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अच्छी स्वच्छता बनाए रखे और साफ-सुथरा रहे, तथा व्यक्तियों को सरकार द्वारा कार्रवाई किए जाने की प्रतीक्षा करने के बजाय भविष्य के बारे में सोचना चाहिए।

राव, एवं अन्य (2015) ^[3] ने स्वच्छ भारत अभियान के प्रभाव और विकास का अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह हर किसी का अवसर और कर्तव्य है कि वह खुले में शौच और अपशिष्ट निपटान के खिलाफ अपनी लड़ाई की घोषणा केवल मैनुअल स्कैवेंजिंग के किसी भी उदाहरण का खुलासा करके करें। बद्र और शर्मा (2015) ^[4] ने अध्ययन किया कि सरकार छात्रों और आम नागरिकों में टीमवर्क और देशभक्ति की भावना पैदा करना चाहती है, और स्वच्छ भारत अभियान के प्रबंधकीय निहितार्थ हैं और निष्कर्ष निकाला कि यह लक्ष्य स्थानीय पहलों में मशहूर हस्तियों की सक्रिय भागीदारी से समर्थित है।

पुलक्कट, एट अल. (2015) ^[5] ने अपने लेख "स्वच्छ भारत अभियान: भारत को साफ करना क्यों गंभीर काम है" में कहा कि स्वच्छ भारत अभियान मुख्य रूप से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और

स्वच्छता पर केंद्रित है। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि भारत सरकार और वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ी समस्याओं में से एक कचरा प्रबंधन है।

स्वच्छ भारत (ग्रामीण) की वर्तमान स्थिति

2001 में केवल 22% ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा थी। संपूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान (एनबीए) में किए गए प्रयासों से यह 2011 की जनगणना के अनुसार 32.70% तक बढ़ गया है। इसके अलावा एनएसएसओ 2012 के अनुसार, 40.60% ग्रामीण परिवारों में शौचालय हैं। स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से 2019 तक सभी ग्रामीण परिवारों को स्वच्छता सुविधाओं से आच्छादित करने की योजना है। सरकार ने 2 अक्टूबर 2019 तक महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक ग्रामीण भारत में 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण करके, 1.96 लाख करोड़ रुपये (यूएस \$ 29 बिलियन) की अनुमानित लागत से खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) भारत प्राप्त करने का निर्णय लिया है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में शौचालयों की आवश्यकता के बारे में बात की थी। मई 2015 तक, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, महिंद्रा ग्रुप और रोटरी इंटरनेशनल सहित 14 कंपनियों ने 3,195 नए शौचालय बनाने का संकल्प लिया है। उसी महीने तक, भारत में 71 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने 86,781 नए शौचालयों के निर्माण का समर्थन किया। इनमें से ज्यादातर शौचालय एक प्रकार के गड्ढे वाले शौचालय हैं, जिनमें से ज्यादातर दोहरे गड्ढे वाले फलश प्रकार के हैं।

अप्रैल 2014 से जनवरी 2015 के बीच 31.83 लाख शौचालय बनाए गए। कार्यक्रम के तहत शौचालय निर्माण में कर्नाटक सभी राज्यों में सबसे आगे रहा। अगस्त 2015 तक, कार्यक्रम के तहत 80 लाख शौचालय बनाए जा चुके हैं। 18 मार्च 2016 तक, भारत के 10 जिले ODF थे।

स्वच्छ भारत मिशन: ग्रामीण क्षेत्र

निर्मल भारत अभियान को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में पुनर्गठित किया गया है। इस मिशन का लक्ष्य पाँच वर्षों में भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाना है। इस मिशन के तहत देश में लगभग 11 करोड़ 11 लाख शौचालयों के निर्माण के लिए एक लाख चौंतीस हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ग्रामीण भारत में कचरे को जैव-उर्वरक और ऊर्जा के विभिन्न रूपों के रूप में धन में बदलने के लिए बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा। इस मिशन को देश की हर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की भागीदारी के साथ युद्ध स्तर पर क्रियान्वित किया जाना है, साथ ही इस प्रयास में ग्रामीण आबादी

के बड़े हिस्से और स्कूली शिक्षकों और छात्रों को भी शामिल किया जाना है।

- अक्टूबर 2014 से 26.12.2020 (2020-2021) तक एसबीएम (जी) के तहत 10.84 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया है। साथ ही, 31 मार्च, 2017 तक मनरेगा के तहत 16.41 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया है।
- 2 अक्टूबर 2014 तक स्वच्छता कवरेज 38.7% था। 26 दिसंबर 2020 (2020-2021) तक यह बढ़कर 61.25% हो गया है।
- 26.12.2020 (2020-2021) तक 711 जिले, 2,62,772 ग्राम पंचायत और 602988 गांव खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित किए जा चुके हैं। 04.07.2019 तक 30
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है।
- स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत केंद्रीय आवंटन क्रमशः 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-2020 में 2850 करोड़ रुपये, 6525 करोड़ रुपये, 10,500 करोड़ रुपये, 14,000 करोड़ रुपये और 34303 करोड़ रुपये, 140881 करोड़ रुपये थे।

लाभ

स्वास्थ्य: अस्वच्छता बीमारियों, व्याधियों के महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। किसी भी बीमारी या रोग का आर्थिक प्रभाव उपभोग और वैकल्पिक आय अर्जन दोनों पर पड़ता है। स्वच्छ भारत मिशन भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। WHO के अध्ययन के अनुसार। स्वच्छता की कमी और स्वच्छता की कमी के कारण हर भारतीय को हर साल 6500 डॉलर का नुकसान होता है। केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन (SBM) ने हर परिवार को सालाना 727 अमेरिकी डॉलर का लाभ देकर बहुत ही किफायती साबित किया है, मुख्य रूप से स्वास्थ्य से जुड़ी बचत जैसे दस्त की आवृत्ति में कमी (55%) और नसबंदी के समय बचत (45%) से, वर्ल्ड डेवलपमेंट जर्नल में प्रकाशित यूनिसेफ के एक अध्ययन में कहा गया है।

पर्यटन: भारत एक ऐसा देश है जहाँ सांस्कृतिक विरासत और समृद्ध इतिहास है। पर्यटन उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 6.6% उत्पादन करता है और 39.5 मिलियन भारतीयों का सीधे इस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। पर्यटन उद्योग 5% भारतीयों के लिए रोजगार पैदा कर सकता है। पर्यटन को बढ़ावा देने में भारत के लिए सबसे बड़ी बाधा स्वच्छता है। जैसा कि हम जानते हैं कि विदेशी पर्यटक स्वच्छता और साफ-सफाई के बारे में विशेष रूप से चिंतित रहते हैं। व्यापार के बाद

पर्यटन उद्योग विदेशी धन को भारत में लाने में मदद करेगा जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का समर्थन करेगा स्वच्छ भारत मिशन पर्यटन उद्योग के माध्यम से रोजगार पैदा करने में मदद करेगा।

शिक्षा: शिक्षा क्षेत्र ने अहम भूमिका निभाई। स्वच्छ भारत मिशन को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शौचालयों की कमी के गंभीर मुद्दों को संबोधित करने के लिए पेश किया गया है। यह भारत में कीटाणुशोधन में व्यक्तिपरक (उपयोग) और मात्रात्मक (विकास) दोनों सुधार पर केंद्रित है। सबसे बड़ी चुनौती जो आगे है वह शौचालयों का निर्माण नहीं बल्कि रखरखाव, पानी की आपूर्ति, साफ-सफाई से जुड़ी स्वच्छता का मुद्दा है। मिशन लोगों में जागरूकता पैदा करके इन चुनौतियों को दूर करने का प्रयास करता है। साथ ही, मिशन में दक्षता और पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए, एक मजबूत निगरानी प्रणाली को लागू करने की आवश्यकता है जो मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सतर्क रहेगी और समय-समय पर मिशन के परिणाम (विकास) और परिणामों (उपयोग) का आकलन करेगी।

एफडीआई: मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार, भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सख्त जरूरत है। भारत ने सिंगापुर से प्रेरणा ली, जिसने 1977 से 1987 तक इसी तरह का स्वच्छता अभियान चलाया था। इसने सिंगापुर को एफडीआई आकर्षित करने में मदद की। उम्मीद है कि स्वच्छ भारत मिशन भारत के लिए भी ऐसा ही कमाल करेगा।

स्वच्छ नवाचार: धीरे-धीरे स्वच्छता और सफाई पर ध्यान केन्द्रित करने से स्वच्छ नवाचार के उपयोग की ओर ध्यान केन्द्रित होगा, जैसे कि प्रकृति में प्रदूषण न हो। इसमें बायोडिग्रेडेबल ईंधन और वस्तुओं का उपयोग शामिल होगा। स्वच्छ नवाचार की ओर कोई भी कदम पूरी अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक और धीरे-धीरे बढ़ता हुआ प्रभाव डालेगा। नया नवाचार सूचना प्रौद्योगिकी के मामले में रोजगार के नए अवसर लेकर आता है। नए नवाचार पर ध्यान केन्द्रित करने से विकास के लिए नई विशेषज्ञता विकसित होगी और इस प्रकार भारत के युवाओं के लिए नए व्यवसाय/उद्यमी स्वतंत्रताएं बनाने में मदद मिलेगी। भारत पूरी दुनिया के लिए स्वच्छ नवाचार का केन्द्र बन सकता है। स्वच्छ भारत मिशन को केवल स्वच्छता और सफाई से ही नहीं जोड़ा जाना चाहिए, बल्कि इसका एक बड़ा उद्देश्य भारत को भविष्य के लिए तकनीकी प्रगति की ओर अग्रसर राष्ट्रों की श्रेणी में लाना है।

स्वच्छ भारत अभियान का प्रभाव

स्वच्छता अभियान का भारतीय समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। लोग गांव, सोसायटी, कॉलोनी, शहर, रेलवे प्लेटफॉर्म आदि को साफ करने की पहल कर रहे हैं। जिला प्रशासन, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को प्रदूषण के खतरों के बारे में जागरूक किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन स्वास्थ्य के मामले में वित्तीय नुकसान को कम करने और मौजूदा स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं पर बोझ को कम करने की कोशिश कर रहा है, जिससे हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। स्वच्छ भारत मिशन हमारे पर्यटन को बढ़ावा देगा। निश्चित रूप से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी क्योंकि पर्यटकों को पहले से बेहतर माहौल मिल रहा है। पर्यटन बढ़ने से हमारी आय अपने आप बढ़ेगी। लेकिन हमारे पास आज भी बहुत से लोग हैं जो जागरूक नहीं हैं। गांवों के लोग, खासकर जो लोग अच्छी तरह से शिक्षित नहीं हैं, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू थूकते हैं। वे बस, ट्रेन में कुछ खाते हैं और पैपर को कूड़ेदान में नहीं बल्कि सड़क पर फेंकते हैं। कुछ लोगों ने अपनी आदतें नहीं बदली हैं। स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए हमें जागरूकता पैदा करने के लिए और अधिक अभियान चलाने की जरूरत है।

स्वच्छ एवं स्वच्छ भारत से उद्योग क्षेत्रों पर अनुमानित आर्थिक प्रभाव

जबकि भारत सरकार स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) की प्रकृति के कार्यक्रम शुरू करती है, और उनका क्रियान्वयन कई हितधारकों द्वारा किया जाता है, जिसका परिणाम विभिन्न उद्योग उप-क्षेत्रों पर पड़ता है। एसबीएम को जब मुख्य घटकों में विभाजित किया जाता है, तो इसका उद्योग पर विविध प्रभाव पड़ता है:

- निर्माण उद्योग,
- उपकरण आपूर्तिकर्ता,
- सेवा प्रदाताओं,
- उपभोक्ता वस्तुओं,
- प्रशिक्षण एवं ज्ञान साझा करने वाली एजेंसियां और
- बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र।

स्वच्छ एवं स्वच्छ भारत से जनशक्ति आवश्यकताओं पर संभावित सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

एस.एम.डब्ल्यू और स्वच्छता क्षेत्र श्रम प्रधान हैं, और अकुशल तथा कुशल श्रम बाजारों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करेंगे। यह अनुमान है कि अकेले व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण के लिए 160 करोड़ व्यक्ति-दिनों की आवश्यकता है; यह महात्मा

गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत उपभोग किए गए व्यक्ति-महीनों के 5-वर्षीय वार्षिक औसत का लगभग 5.5 प्रतिशत है। यह कार्यक्रम स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्रों में विभिन्न सेवा प्रदाताओं को 7,700 करोड़ रुपये के आई.ई.सी. और क्षमता निर्माण के अवसर और 5.5 लाख करोड़ रुपये (दस वर्षों के लिए) के ओ.एंड.एम. अवसर भी प्रदान करता है।

स्वच्छ एवं स्वच्छ भारत का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान और संभावित प्रभाव

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद 106.44 लाख करोड़ रुपये था। इस रिपोर्ट के आधार मामले में एसबीएम और संबंधित घटकों के अनुरूप पांच वर्षों के लिए भारत को स्वच्छ बनाने के लिए अनुमानित निवेश (CAPEX) लगभग 3,89,642 करोड़ रुपये है। यह स्वच्छता व्यय महत्वपूर्ण होने की उम्मीद है और ये अनुमान बताते हैं कि यह अगले पांच वर्षों के लिए वार्षिक आधार पर 0.7 प्रतिशत तक हो सकता है। स्वच्छता में निवेश में यह वृद्धि भारत में अनुमानित 6.4 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद के नुकसान को कम करने का कारण बन सकती है (त्यागी एट अल, 2008)। 2007 में किए गए नुकसान के अनुमान में पर्यावरण प्रदूषण और शमन लागतों का मुद्दीकरण नहीं किया गया था। यह दर्शाता है कि इस रिपोर्ट के अनुमानों के अनुसार अगले पाँच वर्षों में खर्च में वृद्धि होगी, और स्वच्छ भारत निवेश से अर्थव्यवस्था को मिलने वाला रिटर्न, यदि समयबद्ध तरीके से लागू और अपनाया जाए, तो किए गए निवेश से 3-4 गुना हो सकता है। अर्थव्यवस्था और समाज को संभावित रूप से लाभ और भी अधिक हो सकते हैं क्योंकि ऐसे कई लाभ हैं जिन्हें मात्राबद्ध नहीं किया गया है, जिनमें शिशु मृत्यु दर और जलवायु लचीलापन पर संभावित प्रभाव शामिल हैं। यह प्रयास जब अच्छी तरह से योजनाबद्ध किया जाता है, तो यह समानता और गरिमा के मुद्दों को हल करने में मदद कर सकता है।

स्वच्छ भारत अभियान के कारण

डायरिया से हर साल एक लाख से अधिक बच्चों की मौत होती है, स्वच्छता की कमी के कारण बच्चों में शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास में कमी आती है, जिससे भारत में भविष्य में कार्यबल के लिए उनकी उत्पादकता कम हो जाती है और खुले में शौच महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए एक गंभीर खतरा है, जिसे उचित स्वच्छता कार्यक्रम के माध्यम से सुधारा जा सकता है।

सभी के लिए प्रतिज्ञा

माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रत्येक व्यक्ति से निम्नलिखित प्रतिज्ञा लेने का आग्रह किया है: (स्वच्छ भारत पत्रिका, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ)।

“मैं यह प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं स्वच्छता के प्रति समर्पित रहूँगा और इसके लिए समय दूँगा। मैं प्रति वर्ष 100 घंटे, यानी प्रति सप्ताह 2 घंटे, स्वच्छता के लिए स्वैच्छिक कार्य करूँगा। मैं न तो गंदगी करूँगा और न ही दूसरों को करने दूँगा। मैं स्वच्छता की मुहिम की शुरुआत खुद से, अपने परिवार से, अपने मोहल्ले से, अपने गांव से और अपने कार्यस्थल से करूँगा। मेरा मानना है कि दुनिया के जो देश स्वच्छ दिखते हैं, उसका कारण यह है कि वहां के नागरिक न तो गंदगी करते हैं और न ही करने देते हैं। इसी दृढ़ विश्वास के साथ मैं गांव-गांव और कस्बों में स्वच्छ भारत मिशन का संदेश फैलाऊंगा। मैं 100 अन्य लोगों को यह शपथ दिलाने के लिए प्रेरित करूँगा, जो मैं आज ले रहा हूँ। मैं प्रयास करूँगा कि वे स्वच्छता के लिए अपने 100 घंटे समर्पित करें। मुझे विश्वास है कि स्वच्छता की दिशा में उठाया गया मेरा हर कदम मेरे देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा।”—नरेन्द्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री, भारत।

स्वच्छ भारत मिशन: शहरी क्षेत्र

मिशन का लक्ष्य 1.04 करोड़ घरों को कवर करना, 2.5 लाख सामुदायिक शौचालय, 2.6 लाख सार्वजनिक शौचालय और प्रत्येक शहर में एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा प्रदान करना है। कार्यक्रम के तहत, सामुदायिक शौचालय उन आवासीय क्षेत्रों में बनाए जाएंगे जहां व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण करना मुश्किल है। सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण पर्यटन स्थलों, बाजारों, बस स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों आदि जैसे निर्दिष्ट स्थानों पर भी किया जाएगा। कार्यक्रम को 4,401 शहरों में पांच साल की अवधि में लागू किया जाएगा। कार्यक्रम पर खर्च होने वाली संभावित 62,009 करोड़ रुपये में से केंद्र 14,623 करोड़ रुपये देगा। केंद्र के 14,623 करोड़ रुपये के हिस्से में से 7,366 करोड़ रुपये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर, 4,165 करोड़ रुपये व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों पर, 1,828 करोड़ रुपये सार्वजनिक जागरूकता पर और 655 करोड़ रुपये सामुदायिक शौचालयों पर खर्च किए जाएंगे।

- निर्मित व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों की संख्या (2020-2021): 62.64 लाख
- निर्मित सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों की संख्या (2020-2021): 6.20 लाख
- 100% डोर टू डोर कचरा संग्रहण (2020-2021) वाले वार्ड और शहर क्रमशः 83434 और 4372 हैं

- ओडीएफ घोषित (99%): 4371
- ओडीएफ प्रमाणित: 4316
- कचरा मुक्त शहर (2020-2021): 167*, 166***, 9*****

स्वच्छ भारत का वित्तपोषण: स्वच्छ भारत के लिए धन की व्यवस्था

'शौचालय पहले, देवालय बाद में': स्वच्छ भारत मिशन

स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) को प्रधानमंत्री मोदी ने अक्टूबर 2014 में 'शौचालय पहले, मंदिर बाद में' के नारे के साथ शुरू किया था: यह भारत में बेहतर सफाई और स्वच्छता की आवश्यकता की स्वीकृति थी। एसबीएम का मुख्य उद्देश्य खुले में शौच को खत्म करना और 2019 तक सभी भारतीयों को स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करना है। इसलिए केंद्र सरकार (जीओआई) बड़े पैमाने पर निर्माण को सब्सिडी दे रही है: कार्यक्रम के पहले वर्ष में 8.8 मिलियन ग्रामीण शौचालय बनाए गए थे, और शहरी क्षेत्रों में अकेले 2015/16 में 25,000 सामुदायिक शौचालय और 26,000 सार्वजनिक शौचालय बनाए जाने हैं। अपशिष्ट प्रबंधन और व्यवहार परिवर्तन में सुधार पर भी ध्यान दिया जा रहा है। एसबीएम एक महत्वाकांक्षी प्रयास है: 569 मिलियन भारतीय अभी भी खुले में शौच करते हैं। एसबीएम को दो मिशनों में विभाजित किया गया है: एसबीएम में पांच स्तरीय कार्यान्वयन प्रणाली है, जो राष्ट्रीय स्वच्छ भारत मिशन से शुरू होकर राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव स्तर तक जाती है। एसबीएम बहुत अधिक अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित कर रहा है: क्या शीर्ष-स्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता और बड़े पैमाने पर सरकारी निवेश मिलकर निम्न-मध्यम आय वाले देश की विशाल स्वच्छता चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं? हर कोई यही उम्मीद करता है! फिर भी, चुनौतियाँ बहुत बड़ी हैं। क्या एसबीएम वास्तव में स्वच्छता में सुधार करेगा, या यह केवल लाखों निम्न-गुणवत्ता वाले शौचालयों के निर्माण को सब्सिडी देगा? और क्या सरकार वास्तव में कार्यात्मक शहरी स्वच्छता प्रणाली प्राप्त करने के लिए आवश्यक धन जुटा पाएगी?

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में, इस अध्ययन से पता चला है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) वित्तीय और आर्थिक दोनों दृष्टिकोणों से अत्यधिक लागत-लाभकारी है। यहाँ तक कि जो परिवार शौचालय और हाथ धोने के स्टेशन में अपने स्वयं के 16,000 रुपये (यूएस \$248) का निवेश करते हैं, इस वर्तमान अध्ययन ने पूर्ण आर्थिक लाभों (सामाजिक दृष्टिकोण से 4.3 का औसत बीसीआर) के आधार पर आर्थिक प्रतिफल की बहुत ही समान दरें दिखाई। वास्तव में, इस वर्तमान अध्ययन में यह पाया गया कि परिवार -

यहाँ तक कि गरीब परिवार भी - कई हजार रुपये की सरकारी प्रोत्साहन राशि के अलावा अपना खुद का निवेश करते हैं। इसलिए स्वच्छ भारत मिशन को लागू करने के लिए परिवारों के लिए पूर्ण निवेश लागत की पहचान करने के साथ-साथ, इस सर्वेक्षण ने पहले से पहचाने गए लाभों की तुलना में लाभ के स्तर में वृद्धि दर्ज की है - विशेष रूप से चिकित्सा लागत में बचत के लिए।

संदर्भ

1. तिवारी सुरेन्द्र कुमार. निजी और सरकारी स्कूलों के मिडिल स्कूल के छात्रों में राष्ट्रीय मिशन: स्वच्छ भारत: स्वच्छ विद्यालय के बारे में जागरूकता का अध्ययन करना. इंडियन जर्नल ऑफ रिसर्च. 2014;3(12).
2. इवने के. स्वच्छ भारत मिशन और भारत में दलित समुदाय विकास. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स. 2014;2(9).
3. राव सुब्बाराव. स्वच्छ भारत: कुछ मुद्दे और चिंताएँ. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एकेडमिक रिसर्च. 2015;2(4(4)):90-93. उपलब्ध: [http://ijar.org.in/stuff/issues/v2-i4\(4\)/v2-i4\(4\)-a013.pdf](http://ijar.org.in/stuff/issues/v2-i4(4)/v2-i4(4)-a013.pdf).
4. बद्र, शर्मा. स्वच्छ भारत मिशन से प्रबंधन के सबक. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस रिसर्च इन साइंस एंड इंजीनियरिंग. 2015;4:214-220.
5. पुलक्कट एच. स्वच्छ भारत अभियान: भारत को साफ करना क्यों एक गंभीर काम है. ईटी ब्यूरो. 3 मार्च 2015.
6. स्वैन पी, पठेला एस. भारत के दो जिलों में "स्वच्छ भारत अभियान" के संदर्भ में स्वच्छता और स्वच्छता प्रथाओं की स्थिति. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ. 2016;3(11):3140-3146. doi:10.18203/2394-6040.ijcmph20163925.
7. जैन पारस, मलैया सोमन, सिंघई अनुपम जैन. भारत में स्वच्छ भारत अभियान के प्रभाव. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस रिसर्च. 2016;2(10):18-20.
8. प्रधान पी. स्वच्छ भारत अभियान और भारतीय मीडिया. समुदाय और संचार, एमिटी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन. 2017;5. ISSN: 2456-9011.
9. चिंचवडकर पी, उदयई के, पटनायक जे. महिलाओं की जागरूकता, स्वीकार्यता और ग्रहणशीलता "स्वच्छ भारत का शौचालय अभियान": एक क्रॉस-सेक्शनल मूल्यांकन. 2017;2:3-7.
10. सिंह एसएल, कुंवर एन, शर्मा ए. भारतीय समाज में स्वच्छ भारत अभियान का प्रभाव. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ होम साइंस. 2018;4(1, भाग D):215-219.
11. खरेल एस, शरीफ एमजे, रवींद्रनाथ एस, विद्या ए, राज केजी. स्मार्ट शहरों के विकास और स्वच्छता प्रोफाइल पर एक अध्ययन - तिरुचिरापल्ली शहर का एक केस स्टडी. फोटोग्रामेट्री, रिमोट सेंसिंग और स्थानिक सूचना विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार. 2018;XLII-5(नवंबर):741-748. doi:10.5194/isprs-archives-xlii-5-741-2018.
12. प्रजापति एसजी. गुजरात में महात्मा गांधी स्वच्छता मिशन: मार्केटिंग रणनीतियाँ और मीडिया उपयोग एक महत्वपूर्ण विश्लेषण. जर्नल ऑफ एडवांस मैनेजमेंट रिसर्च. 2018;6(3):259-268.
13. भट्टाचार्य एस, शर्मा डी, शर्मा पी. स्वच्छ भारत मिशन: भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरनमेंट एंड हेल्थ (IJENVH). 2018;9(2):197-[पूरा पृष्ठ नहीं दिया गया].
14. राय जी, चक्रवर्ती ए, दास एन. स्वच्छता की स्थिति: पश्चिम बंगाल के ग्रामीण सुंदरबन का एक केस स्टडी. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स (IJCRT). 2019;7(2):734-740.
15. दंडबथुला जी, भारद्वाज पी, बुरा एम, राव पीवी, राव एसएस. भारत के स्वच्छ भारत मिशन - स्वच्छ भारत अभियान का तीव्र दस्त रोग प्रकोप पर प्रभाव आकलन: हाँ, एक सकारात्मक बदलाव है. जे फैमिली मेड प्राइम केयर. 2019;8:1202-1208.

Creative Commons (CC) License

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.